

नागरिकता संशोधन कानून पर सतर्कता जरूरी

जी. पार्थसारथी
कोई हैरानी नहीं कि 11 दिसम्बर को संसद में पारित हुए नागरिकता संशोधन कानून के बाद देश और विदेश में बवाल खड़ा हो गया। इस कानून के तहत खासतौर पर तीन पड़ोसी मुस्लिम देशों यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों जैसे कि हिंदू-सिख-बौद्ध-जैन-पारसी और ईसाई शरणागतों को नागरिकता प्रदान करने की राह खुल गई है। हालांकि यह कानून मोटे तौर पर पाकिस्तान से आने वाले गैर-मुस्लिम शरणार्थियों के लिए है तथापि इस पर बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी क्षुब्ध हुए हैं। अनुमान के मुताबिक 25,400 हिंदू, 5,800 सिख और 100 ईसाईयों को इससे फौरी लाभ मिलेगा, जो अधिकांशतः पाकिस्तान से हमारे यहां आए हैं। रोचक बात है कि पाकिस्तान में अतिवादी सुन्नी हिंसा का ज्यादातर शिकार कादियानी (अहमदिया) मुस्लिम बनते आए हैं, वहां इन पर विधर्मी और शियापरस्त होने का ठप्पा लगाया जाता है। अफगानिस्तान की प्रतिक्रिया आशा के अनुरूप आई है। उसका कहना है कि सत्ता से तालिबान के हटने के बाद देश में सिख और हिंदू समाज खुशनुमा और समृद्ध जिंदगी बसर कर रहे हैं। यहां यह भी ध्यान में रखने की बात है कि भारत में रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थियों का दर्जा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त शरणार्थी का है, जो म्यांमार में धार्मिक प्रताड़ना के बाद भागकर आए हैं।

दक्षिण एशिया के देशों में बांग्लादेश की वर्तमान शेख हसीना सरकार भारत के

प्रति बिना शक सबसे ज्यादा मैत्रीपूर्ण है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें अपने देश के अंदर भारत के नवीनतम कानून की वजह से कड़ी आलोचना सहनी पड़ रही है। हालांकि शेख हसीना ने बहुत दक्षता से भारत और चीन के साथ बांग्लादेश के संबंधों का संतुलन बनाकर दोनों के साथ अच्छे संबंध बना रखे हैं। रावलपिंडी स्थित पाक-सेना मुख्यालय और इस्लामाबाद में बैठी पाकिस्तानी सरकार के लिए बांग्लादेश में एक कट्टरवादी सरकार का बनना भारत को चुनौती देने में आदर्श स्थिति होगी। हमारे सामने यह सुनिश्चित करने की गंभीर चुनौती है कि किस तरह शेख हसीना अपने देश में पाकिस्तान-परस्त कट्टर तत्वों के दबाव में न आने पाएं, क्योंकि ये लोग हौवा खड़ा करेंगे कि भारत से बड़ी संख्या में बंगाली मुसलमानों को खदेड़ा जाएगा और इसकी आड़ में भारत से संबंध बिगाड़ने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे। शेख हसीना ने इस आशंका के मद्देनजर हमारे नवीनतम कानून पर पहले ही अपनी असहजता और नाराजगी भरा कड़ा संकेत दे दिया है। इसका पता बांग्लादेश के विदेशमंत्री और गृहमंत्री की भारत यात्रा को स्थगित किए जाने से चलता है।

हालिया घोषणा से हमारे उत्तर-पूर्वी राज्यों में भी एक बार फिर से तनाव का माहौल बन गया है, विशेषकर असम और त्रिपुरा में, जहां के मूल निवासी अल्पसंख्या में आ चुके हैं। वहां 1980 के दशक में हुए 'विदेशी भगाओ' आंदोलनों की तर्ज पर फिर से मुहिम चलाने की बात होने लगी है। इसी के चलते सशस्त्र विद्रोही गुट जैसे

कि उल्फा जैसे संगठनों का जन्म हुआ था, जिन्होंने बेगम खालिदा जिया की सत्ता के वक्त बांग्लादेश और म्यांमार-चीन सीमा के अंदर अपने सुरक्षित अड्डे बना रखे थे। यह सब घटनाक्रम उस वक्त हो रहा है जब हम अपने उत्तर-पूर्वी राज्यों में सशस्त्र विद्रोही गुटों को काफी हद तक हाशिए पर ढकेलने में कामयाब हो चुके हैं। यहां हमें यह भी ध्यान में रखना है कि चीन के युनान प्रांत में बैठे चीनी अधिकारियों और म्यांमार-भारत से विद्रोह कर रहे सशस्त्र गुटों के बीच सक्रिय संपर्कों और सहयोग में इजाफा होता जा रहा है। चीन वस्तुतः म्यांमार और भारत के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है। वह म्यांमार सरकार और सशस्त्र विद्रोही गुटों के बीच खुद को मध्यस्थ बना रहा है। इन चुनौतियों को संवेदनशीलता किंतु दृढ़ता से निपटना होगा।

उधर ट्रंप प्रशासन अगले साल अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले किसी भी तरह अफगानिस्तान में तैनात अपने सैनिकों को वापस बुलाने को दृढ़संकल्प है। उस सूरत में पाकिस्तान बड़े शांतिराना तरीके से ड्यूरेड सीमा रेखा से सटे अफगानी इलाकों को अपने अपरोक्ष नियंत्रण में करने हेतु अपने यहां पाले-पोसे आतंकी गुट हक़ानी नेटवर्क का इस्तेमाल करेगा।

बेशक भारत की ख्याति एक ऐसे लोकतांत्रिक समाज की है जहां मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए बराबर के मौके सुनिश्चित हैं। हमारे पड़ोसी देशों के लोगों में बनी यह साख लगातार बनी

रहनी चाहिए और इस हेतु कुछ ठोस तथ्य ध्यान में रखने होंगे। यूं तो विश्वभर में मुसलमानों की गिनती लगभग 1.8 अरब है और तुर्की से लेकर इंडोनेशिया के बीच के इलाके में 80 करोड़ मुस्लिम लोग बसे हुए हैं। इस्लामिक पट्टी में भी हमारी काफी इज्जत है, जैसे कि अनेकानेक मुद्दों पर हमें मिला उनका समर्थन दर्शाता है। जिन देशों में मुसलमानों की तादाद काफी ज्यादा है, उनमें इंडोनेशिया (26.8 करोड़), पाकिस्तान (20 करोड़), भारत (19.5 करोड़) और बांग्लादेश (15.37 करोड़) हैं। विश्व भर के मुसलमानों का लगभग एक-तिहाई दक्षिण एशियाई मुल्कों में रहता है।

कश्मीर घाटी में कथित भारतीय नाकाबंदी को लेकर पाकिस्तान पहले से ही कूटनीतिक लड़ाई में लिप्त है। अब हमारे नए नागरिकता संशोधन कानून की घोषणा के बाद बिना शक और ज्यादा सक्रिय हो जाएगा, खासकर अफगानिस्तान में इस दावे के साथ कि भारत की नीतियां अफगान मुस्लिमों के प्रति भी दुराग्रहपूर्ण हैं। हिंद महासागर क्षेत्र के अन्य मुस्लिम देशों में भारत को नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तान पूरा जोर लगा देगा।

खाड़ी देशों में भारत के लगभग 70 लाख कामगार रोजगार में लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े सुनियोजित तरीके से अरब मुल्कों के साथ भारत के रिश्तों को पूरी तरह बदलकर रख दिया है, खासकर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात पर विशेष ध्यान देकर। किंतु उक्त अरब देशों के सामने तुर्की के नेतृत्व में ऐसा एक गठजोड़ है, जो भारत की छवि बतौर एक मुस्लिम-

विरोधी देश पेश कर रहे हैं। इस गुट के मलेशिया, कतर और ईरान ज्यादा मुखर सदस्य हैं और पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान भी इसमें अवश्य शामिल होगा।

हालांकि भारत के साथ किस तरह बरतना है, इसको लेकर पश्चिमी जगत आपस में बंटता लगता है। अमेरिका में भारत के संबंध रिपब्लिकन दल के साथ ज्यादा सहज लग रहे हैं क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ गुट हमारे खिलाफ भावना रखते हैं। ब्रिटेन की सत्ता में कंजर्वेटिव पार्टी की वापसी से हमें खुशी हुई है, वहां भारत-विरोधी भावना रखने वाली लेबर पार्टी को मतदाताओं ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया है।

हालांकि अपने देश के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत बनी नई स्थिति को लेकर हमें बाकी देशों के सामने शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। परंतु जब मैं विश्वभर से आई प्रतिक्रियाओं का आकलन करता हूँ, जैसे कि दूरदराज प्रशांत महासागर के तट पर बसे कैलिफोर्निया से, जहां भारत से गए उच्च-तकनीक विशेषज्ञ काफी बड़ी संख्या में मौजूद हैं, तो दो मुद्दों पर बनी वास्तविक अंतरराष्ट्रीय चिंता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पहली, कश्मीर में काफी लंबे समय से सक्रिय रहे राजनेताओं की जारी नजरबंदी और दूसरी है वहां अन्य प्रतिबंधों का आज भी लागू रहना, जिसमें कोई नागरिक आंदोलन शुरू होते ही इंटरनेट, मोबाइल फोन, ई-मेल एवं अन्य संचार सुविधाओं को बंद करना अनुचित है। उम्मीद है इन दोनों विषयों को ज्यादा कल्पनाशीलता से हल किया जाएगा।

सोरेन का शपथ ग्रहण संपादकीय

हेमंत सोरेन का झारखंड में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण समारोह विपक्षी एकजुटता का मौका बन गया। इसे आदिवासियों के उन्नायक बिरसामंडा के विचारों की लीक पर चलने वाली सरकार बताया जा रहा है। उनके साथ मंत्रिपद की शपथ लेने वालों में दो कांग्रेस व एक आरजेडी विधायक भी शामिल थे। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने पद-व गोपनीयता की शपथ 44 वर्षीय हेमंत सोरेन को दिलायी।

हेमंत दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। इस 81 सदस्यीय विधानसभा में झामुमो के तीस व सहयोगी कांग्रेस के 16 व राजद के एक विधायक हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने शपथ ग्रहण समारोह को विपक्षी शक्ति प्रदर्शन के अवसर में बदलने का प्रयास किया। जहां कांग्रेस की ओर से पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने समारोह में हिस्सा लिया, वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी, डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, राजद नेता तेजस्वी यादव ने हिस्सा लिया। वाम दलों की ओर से सीताराम येचुरी और डी. राजा तथा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत

तथा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी समारोह में शामिल हुए। विपक्षी एकजुटता के दावों को उस समय झटका लगा, जब पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, महाराष्ट्र के



मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समारोह में भाग लेने नहीं पहुंचे। सपा अध्यक्ष व उ.प्र. के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व बसपा सुप्रीमो मायावती भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए।

शपथ ग्रहण से पूर्व ही एनआरसी पर कड़ा बयान देकर सोरेन ने दिल्ली सरकार को सख्त संदेश दिया। उन्होंने राज्य में एनआरसी लागू न करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है और हम अव्यावहारिक एनआरसी के मुद्दे पर उलझे हुए हैं। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस विधायक आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव और

आरजेडी विधायक सत्यानंद भोक्ता ने भी मंत्रिपद की शपथ ली। आलमगीर झारखंड विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं। उन्होंने पाकुड़ विधानसभा सीट से जीत दर्ज की। वे झारखंड विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। रामेश्वर उरांव झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वे लोहरदगा विधानसभा सीट से जीते हैं। उरांव केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि, इस मौके को विपक्षी एकजुटता का अवसर बनाने का प्रयास किया, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर किसी बड़े प्रभाव का कोई संकेत पहली नजर में नहीं दिखायी देता। मोरहाबादी मैदान में हुए भव्य आयोजन के दौरान शिबू सोरेन का कहना था कि झारखंड में सरकार बनने का असर पूरे देश पर होगा। उन्होंने कहा कि नयी सरकार को शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। उम्मीद जतायी जा रही है कि सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कुछ अहम फैसले लिये जा सकते हैं। इसमें किसानों की ऋण माफी भी शामिल हो सकती है। निःसंदेह सोरेन परिवार के आधी सदी के संघर्ष की विरासत के वारिस हेमंत सोरेन के सिर पर झारखंड का ताज सजने के बाद आदिवासी समाज में विकास की उम्मीदें बढ़ गई हैं।

सू-दोकू क्र.96							
	6	3		8		1	4
8			3		4		7
	4			5		8	
3		8			1		4
	1			4		9	7
		4			2		1
1				3		4	8
	8		2		9		3
		9		1		2	5

नियम	सू-दोकू क्र.95 का हल								
1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गों का एक खंड बनता है।	6	7	9	2	4	5	3	1	8
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक भर सकते है।	2	1	8	3	7	6	9	5	4
3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।	7	6	4	5	2	8	1	3	9
	3	8	1	6	9	7	2	4	5
	9	2	5	4	1	3	8	6	7
	8	3	7	9	6	4	5	2	1
	5	4	2	8	3	1	7	9	6
	1	9	6	7	5	2	4	8	3
	4	5	3	1	8	9	6	7	2